Statement

The Statewise Estimated members of Memoranda filed by the entrepreneurs for Establishment of new undertakings/Effecting Substantial Expansion for processing liquid milk and manufacture of milk products

States	Estimated member of Memoranda filed
Andhra Pradesh	18
Delhi	8
Gujarat	27
Haryana	115
Himachal Pradesh	5
Kerala	2
Karnataka	4
Madhya Pradesh	25
Maharashtra	42
Punjab	54
Rajasthan	47
Tamil Nadu	7
Uttar Pradesh	164
West Bengal	2
TOTAL	520

Setting Up of Food Processing Units in Arunachal Pradesh

400. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Arunachal Pradesh is lagging far behind many States in the field of food processing industries ;

(b) whether there is good scope to set up food processing units particularly for fruits and vegetables in the State ; and

(c) what are details of steps that are being taken by Central Government to set up such units in Arunachal Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) While this Ministry does not directly set up food processing units in any State, several developmental plan schemes have been formulated to provide assistance to State Government organisations/cooperatives/joints sector etc., for setting up or enlarging food processing units in the States.

शीतल पेयों का उत्पादन करने की अनुमति मांगने वाली विदेशी कम्पनियां

401. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत सरकार से भारत में शीतल पेयों का उत्पादन करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है

जिन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है और इस संबंध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) प्रसंस्कृत एक्सट्रूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स और गैरएल्कोहालिक पेय, वेस/सुगंध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूड्स प्रा० लि०" नामक एक नई कंपनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै० जे० एण्ड० आर० पी० कं० लि० और 40 प्रतिशत इक्विटी वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साऊथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेन्सी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार ने मंजूरी दी है । यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अलावा भारत में मृदु पेय तैयार करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेने के संबंध में विदेशी कंपनी से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Cancellation of election to Rajya Sabha

402. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the biennial elections to Rajya Sabha/Legislative Council held recently on the 25th June, 1992 in Bihar have been held void ; and

(b) if so, what are the reasons and grounds therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) The following main reasons have been given by the Election Commission in its order dated 1st July, 1992 for holding the elections void :

(i) The orderly conduct of the poll was disturbed due to the unregulated flow of voters and the frequent entry of unauthorised persons into the polling station including among others the Chief Minister and the Leader of the Opposition along with many others.

(ii) The poll proceedings were frequently interrupted by incidence and scuffles inside the polling station.

(iii) The exercise of the electoral rights by at least two, if not more, voters was interfered with by the snatching of their ballot papers and marking thereof by unauthorised persons.

(iv) The secrecy of vote was violated due to open voting, snatching of ballot papers and their forcible marking.

लिखित बहस प्रणाली

403. डॉ० बापू कालदाते : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी न्याय-प्रणाली को अंगीकार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि लिखित तर्क से समय की बचत होगी तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या में भी कमी आएगी ;

(घ) इसे कब तक अंगीकार कर लिया जाएगा ; और

(ङ) यदि लिखित तर्क प्रणाली को अंगीकार कर लिया जाएगा तो उस दशा में इन सभी मामलों का निपटान कब तक हो जाएगा ?